nomically cleared by CEA on 14.3.1991. The investment decision of the same is still awaited.

The following new thermal power projects are presently under examination in CEA:—

S. No.	Name of Scheme	Capacity (MW)	Executing Agency
1	Suratgarh TPS Stage II . .	2x250	RSEB
2	Kota TPS Stage IV . . .	1x210	RSEB
3	Chittorgarh TPS . . .	1x500	M/s. Century Textiles Industries.
4	Dholpur TPS	2x350	M/s. RPG Enterprises.

The details of thermal power projects under execution in Rajasthan are as follows :—

S. No.	Project Name	Capacity	Commissioning Schedule as now expected	Cost (Rs. Lakhs) Orig.	Latest	Escalation (%age)
STATE SECTOR						
1	Ramgarh GT	3	11 94 (Actual)	394	1271	877 (223%)
2	Suratgarh TPP . . .	2x250	U1 97-98 U2 98-99	125331	125331	..
3	Ramgarh GT Extn. . . .	35.5	3/95	12083	12083	..
CENTRAL SECTOR						
1	Barsingsar Lignite . . . (Neyveli Lignite Corporation)	2x120	*	56573	66411	9838 (17%)

* Not known as the order for main plant and equipment has not been placed.

(c) Only one new hydel project namely Jakham H.E. Project (2x2.5 MW) at an estimated cost of 1778 lakhs is likely to be started w.e.f. 1995-96. The Jakham Project (2x2.5 MW) is being established near village Anoopura in Chittorgarh District. The Project has been cleared from forest angle on 7.11.1994.

(d) The National Wind Resource Assessment Programme is in operation in the state of Rajasthan to assess the wind power potential. No potential sites have been identified so far for generation of wind power in the state. The Wind Power Project would be considered only after potential sites are identified.

मध्य प्रदेश में विद्युत परियोजनाएं

1189. श्री अजीत जोगी :
श्री मलयचन्द मीणा :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश में स्थापित की जाने वाली कतिपय गैस, जल और ताप विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में निर्माण कार्य कब तक आरम्भ किए जाने की सम्भावना है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) विभिन्न राज्यों में विद्युत उत्पादन के सम्बन्ध में अब तक कितनी विदेशी कम्पनियों के साथ सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं और तत्सम्बन्धी प्रमुख विशेषताएं और शर्तें क्या-क्या हैं ; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप विद्युत उत्पादन की कुल क्षमता कितनी हो जाएगी और इससे किस सीमा तक राष्ट्र की आवश्यकता पूरी हो जाएगी ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला चिमनभाई पटेल) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश के राज्य क्षेत्र में अनुमोदित और प्रचालनाधीन स्कीमें निम्नलिखित हैं :—

क्र० सं०	परियोजना का नाम	क्षमता (मे०वा०)
1	2	3
	जल विद्युत	
1.	बाणेसागर–4	
2.	बाणसागर टोन्स	30
	बाणसागर टोन्स	60
	हसदेव बांगो	120
	नर्मदा सागर .	1000
6.	राजघाट (58%) .	22.5
7.	सरदार सरोवर (57%)	684
8.	सरदार सरोवर (57%)	142.5
	ताप विद्युत	
9.	बिरसिंहपुर विस्तार .	420
10.	बिरसिंहपुर यूनिट 1 एवं 2 .	420

उपरोक्त के अलावा, मारिखेड़ा एच ई पी और ओंकारेश्वर जल विद्युत परियोजना को भी केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी आर्थिक दृष्टिकोण से स्वीकृत कर दिया गया है तथा निवेश अनुमोदन के पश्चात् इन परियोजनाओं पर कार्य आरम्भ किया जाएगा । महेश्वर जल विद्युत परियोजना, जिसे भी सी ई ए द्वारा तकनीकी आर्थिक दृष्टिकोण से स्वीकृत कर दिया गया है, राज्य सरकार द्वारा एक निजी प्रवर्तक को सौंप दी गई है ।

विन्ध्याचल एस टी पी एस–2 (1000 मे०वा०) का क्रियान्वयनन केन्द्रीय क्षेत्र में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा किया जा रहा है ।

(ग) अभी तक निजी क्षेत्र में 30,524 मे०वा० की क्षमता अभिवृद्धि हेतु 40 विद्युत परियोजनाओं को स्थापित किए जाने के लिए 40 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिनमें विदेशी निवेश (एनआरआई और संयुक्त उद्यम प्रस्तावों सहित) अन्तर्निहित है । ये समझौता ज्ञापन सामान्य तौर पर प्रवर्तकों को परियोजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत करते हैं तथा इन स्वीकृतियों को प्राप्त करने में सम्बन्धित राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों और प्रवर्तकों की देयताओं का निर्धारण करते है ।

(घ) अभी उन परियोजनाओं की संख्या के बारे में नहीं बताया जा सकता जो पूरी होने वाली हैं ।

Selection of promoters for private sector power projects

1190. SHRI T. VENKATRAM REDDY: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) what is the policy of selecting promoters for power generation in the private sector; and

(b) how many projects can one promoter get?